

प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, इलाहाबाद।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
3. समस्त अधीक्षक/प्रमारी चिकित्सा अधिकारी
सामु0/प्रा0 स्वा0 केन्द्र, इलाहाबाद।
4. मुख्य अधिशाषी अधिकारी
छावनी परिषद-इलाहाबाद।
5. समस्त अधिशाषी अधिकारी नगर निगम, इलाहाबाद।
झूँसी, हण्डिया, मऊआइमा, फूलपुर, लालगोपालगंज, शंकरगढ़, सिरसा, भारतगंज एवं
कोरांव।

पत्रांक: वी0एस0/(जन्म-मृत्यु) पंजीकरण/2015-16/
महोदय,

दिनांक: 11/05/2015

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन
लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-24फ/वी0एस0/सर्कुलर-92/2015/588 लखनऊ दिनांक:
23/04/2015 जो कि मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या:
349/2008 वास्तुयुक्ती हेल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 13/01/2015 को जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित आदेश के
अनुपालन में है, को अवलोकन करें।

इस सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में दिये निर्देशों का कड़ाई
से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें एवं प्रत्येक माह रिपोर्ट भेजवाना
सुनिश्चित करें।

संलग्नक: पत्र की छायाप्रति।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद।
तद्दिनांक

पत्रांक: वी0एस0/(जन्म-मृत्यु) पंजीकरण/2015-16/1036

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन लखनऊ
को उनके पत्र संख्या-24फ/वी0एस0/सर्कुलर-92/2015/588 लखनऊ दिनांक:
23/04/2015 के सदर्थ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद।
3. नगर आयुक्त, नगर-निगम इलाहाबाद।
4. मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
5. जिला विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी-इलाहाबाद को इस आशय से कि संलग्नक पत्र के अनुसार
कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ रजिस्ट्रार को अपने स्तर से निर्देश जारी करने का कट
करें।
7. इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन, इलाहाबाद को इस आशय से कि संलग्नक पत्र के गम्भीरता
को देखते हुए अपने स्तर से समस्त प्राइवेट चिकित्सालय एवं नर्सिंग होम को निर्देश जारी करें
कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण में सहयोग प्रदान करें अन्यथा उनके पंजीकरण के सन्दर्भ में पुनर्विचार
करना पड़ेगा।
8. प्राइवेट चिकित्सालय / नर्सिंग होम एसोसिएशन, इलाहाबाद को इस आशय से कि अपने स्तर
से संलग्नक पत्र के अनुसार कार्यवाही करने हेतु दिशा-निर्देश जारी करें।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
इलाहाबाद।

प्रेषक,

मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /
महानिदेशक,
शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) /
जिला अधिकारी, उ0प्र0।

पत्र संख्या:

24फ/वी0एस0/सर्वुलर-92/2015/502

लखनऊ: दिनांक 23 अप्रैल, 2015

विषय :

मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या: 349/2006 वॉल्युण्टरी हेल्थ एसोसिएशन
आफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 13.01.2015 को
जन्म पंजीकरण से सम्बन्धित आदेश के अनुपालन विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पी0सी0पी0एन0डी0टी0अधिनियम-1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, जगत नारायण रोड, लखनऊ के पत्र संख्या: पक/10-जे0डी/202(Vol.II)/2015/502, दिनांक 21.01.2015 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका (सिविल) संख्या: 349/2006 वॉल्युण्टरी हेल्थ एसोसिएशन आफ पंजाब बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा दिनांक: 13.01.2015 को जन्म पंजीकरण पर निम्न आदेश भारत किये गये हैं-

"Quite apart from, the above it is directed that the state of U.P. shall issue a circular requiring the competent authorities as nominated by it to Register the births of children(male or female) at the time of birth so as to effectively show the progress of regress of the sex ratio. We have been compelled to issue such a direction as Mr. Gonsalves learned senior counsel appearing for the petitioner would contend with vehemence that the State of Uttar Pradesh has not taken pains to get such registration done. If the state of Uttar Pradesh has already taken such steps in accordance with law, it shall be put on record by way of an affidavit duly sworn to by the Principal Secretary, Department of Health and, if not, the same shall be complied with as directed hereinabove.

It is directed that the sex ratio shall be maintained district-wise so that it would be appreciated in which district the ratio is not properly maintained and accordingly steps can be taken."

उपरोक्त वर्णित रिट याचिका में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत उ0प्र0राज्य के लिंगीय अनुपात के आंकड़े कमेटी द्वारा सत्यापित किये गये, माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये कि "प्रदेश में होने वाले प्रत्येक जन्म का पंजीकरण करते समय लिंगीय अनुपात का बढ़ना अथवा घटना दर्शाया जाये ताकि प्रत्येक रजिस्ट्रेशन से यह तथ्य उभर कर आये कि प्रदेश में लिंगीय अनुपात बढ़ रहा है या कम हो रहा है। इसके अतिरिक्त जनपदवार लिंगीय अनुपात तैयार किया जाना चाहिये ताकि यह पता लग सके कि अनुक जनपद में वह लिंगीय अनुपात समुचित रूप से तैयार नहीं किया जा रहा है। तदनुसार ऐसे जनपदों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।"

इस सम्बन्ध में कहना है कि राज्य में लिंगीय अनुपात के लगातार अव्यवस्थित अनुपात को दृष्टिगत जनमानस में जागरूकता लाने वाले आवश्यकता है ताकि पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की लगातार कम हो रही संख्या पर अकुशल लगाया जा सके। प्रायः यह तथ्य प्रकाश में आता है कि लड़कियों को जन्म का पंजीकरण नहीं कराया जाता है। अतः अपने अधीनस्थ चिकित्सा संस्थानों/पंजीयन ईकाईयों के रजिस्ट्रारों को अपने स्तर से इस आशय के निर्देश निर्गत करे कि वह अपनी अधिकारिता में होने वाले एक्टों का पंजीयन करते हये लिंगीय अनुपात की सूचनाओं का संकलन/प्रेषण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करे ताकि वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सके एवं उसके परिपेक्ष में सुधार हेतु ठोस कदम उठाये जा सके।

अवगत करना है कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम को प्रभावी, सरल एवं नागरिकों के लिये सुविधाजनक बनाने के लिये समय-समय पर भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली तथा महानिदेशालय स्तर से सर्कुलर/आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं, उदाहरणार्थ पत्र संख्या: 24फ/वी0एस0/कार्यवृत्त/2014/973, दिनांक 15.09.2014 के द्वारा भी दिनांक 11.01.2014 को भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला में निर्गीत बिन्दुओं/सुझावों से अवगत कराया गया था कि "भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2020 तक जन्म-मृत्यु पंजीकरण के शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति का टारगेट निर्धारित किया गया है, वर्तमान में नागरिक पंजीकरण का जो स्तर है वह पर्याप्त नहीं है।

(सु0पा0उ0)

1265
Dr. L. M. K. Singh
21/1/15

S. D. Singh
21/1/15

सूचनाओं के प्रेषण की विधि अद्यतन करके है। इसके लिए जिन जनपदों के जन-मृत्यु प्रयोग नहीं हो रहा है, जिनका प्रेषण का स्तर सुचारु है (नियमित रूप से) का प्रेषण न करने वाले जनपदों को महानिदेशालय स्तर पर प्रेषण ग्राह अनुस्मरण पत्रों के माध्यम से स्थिति से अवगत की जायेगी। यदि इसका कारण बता कर निराकरण किया जाये, जनपदों के साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि समस्त स्थानों पर संचालित नू हुयी जन्म और मृत्यु की सूचना का निश्चित समयावधि में पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए सूचना को जनपद स्तर से मुख्य सचिव कार्यालय में किया जाये।

जनपद स्तर पर अनौपचारिक समन्वय समिति का गठन करते हुए समिति को बैठक प्रत्येक माह अथवा विमाही स्तर पर आयोजित करते हुए कार्यक्रम का प्रगती अनुसंधान किया जाये, इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर जन-मृत्यु पंजीकरण मूल्यांकन एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ को गठन हेतु महानिदेशालय से पत्र संख्या: 246/वीएसओ/स्थापना/2014/अड, दिनांक: 10.04.2014 के द्वारा निर्देशित भी किया गया था।

जन-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यव्यापी सूचनाओं के प्रेषण हेतु निर्धारित 63 प्रकोष्ठ (23 तालिका-जन्म, 21 तालिका-मृत्यु, 7 तालिका-मृत जन्म, 2 तालिका-ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र रिपोर्टिंग स्तर की) को उपलब्ध कराते हुए सूचनाओं के प्रेषण हेतु निर्देशित किया गया परन्तु पंजीयन स्थिति में अपेक्षित सुधार परिलक्षित प्रतीत नहीं हो रहा है, जिसके अनुपालन में निर्देशित किया गया कि जनपद स्तरीय अधिकारी अपनी अधिकारिता में स्थित विभिन्न संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करें तथा जिन संस्थानों के द्वारा सूचनाओं का प्रेषण अथवा संचालन में होने वाली घटनाओं का पंजीकरण नहीं किया जा रहा है, उन्हें चिन्हित करते हुए जन-मृत्यु सचिवालय अधिनियम-1969 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अन्तर्गत सुधारा लाने पर दृष्टित करें।

आ. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 13.01.2015 तथा महानिदेशालय एवं भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली एवं जनसंख्या कार्य निदेशालय, उओप्रओ के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अन्तर्गत अनुसंधान है कि अपने जनपद में जन-मृत्यु पंजीकरण कार्यक्रम का व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान/मूल्यांकन करते हुए प्राप्त निर्देशों का अनुपालन तथा जन-मृत्यु सचिवालय अधिनियम-1969 का पूर्णतया क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें ताकि सूचनाओं का महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2020 तक शत-प्रतिशत पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। (ए. माननीय न्यायालय में राज्य की छवि सुनिश्चित न हो) इसके लिए उचित प्रचार-की आवश्यकता एवं आपके पूर्ण सहयोग आवश्यक है। इस सम्बन्ध में कृपया कार्यवाही से अवगत करवाते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय, नई दिल्ली एवं जनसंख्या कार्य निदेशालय, उओप्रओ एवं उच्चतम न्यायालय में राज्य समुचित प्राधिकरण (पीओसीपीओएनओडीओ अधिनियम-1994) परिवार कल्याण महानिदेशालय, उओप्रओ, जगत नारायण रोड, लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके आदेशों के अनुपालन में अवगत करवाया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

महनीय
 10/04/2015
 उपमुख्य सचिव (जन-मृत्यु)
 संयुक्त निदेशक (वीएसओ)

पत्र संख्या: 246/वीएसओ/सकलर-02/2015/589-96

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
1. उपमहारजिस्ट्रार (सीओसरओएसओ), भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, वीएसओडिवीजन, वेस्ट ब्लॉक-1, आरओकेओपुरम्, नई दिल्ली-110006
 2. सहायक महारजिस्ट्रार (सीआरएस)/संयुक्त निदेशक, जनगणना भवन, प्लाट नओ-सीओसीओ-1, सेक्टर-जी, अलीगंज, लखनऊ, पिन-22724
 3. अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण (पीओसीपीओएनओडीओ अधिनियम-1994), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उओप्रओ, जगत नारायण रोड, लखनऊ-226023
 4. सहायक उपर मुख्य सचिव (जन-मृत्यु)/उपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उओप्रओ।
 5. श्री विनोद कुमार सिंह, उप सचिव चिकित्सा अनुभाग-7, उओप्रओशासन विकास भवन, लखनऊ।
 6. सहायक अधिकारी महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, उओप्रओ, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
 7. श्री वीएसओ लोमर, संयुक्त निदेशक (परिवार कल्याण), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उओप्रओ, जगत नारायण रोड, लखनऊ-226003
 8. सहायक उपर जिला सचिव (जन-मृत्यु)/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उओप्रओ को इस आशय से कि वह अपने स्तर से भी प्राप्त निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित कराये तथा कृपया कार्यवाही से अवगत कराये।

उपमुख्य सचिव (जन-मृत्यु)
 संयुक्त निदेशक (वीएसओ),
 स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।